Date – 2 July 2022

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस

- सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस के कार्य और योगदान के सम्मान में भारत हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इस उद्देश्य के लिए स्थापित पुरस्कारों के माध्यम से व्यावहारिक और सैद्धांतिक सांख्यिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता अनुसंधान द्वारा आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।

मुख्य विशेषताएं:

उद्देश्य:

- दैनिक जीवन में आँकड़ों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और नीतियों को आकार देने और तैयार करने में सांख्यिकी कैसे मदद करती है, इस बारे में जनता को जागरूक करना।
- सामाजिक-आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जन जागरूकता बढ़ाना।
- **वर्ष 2022 के लिए थीम:** 'सतत विकास के लिए सांख्यिकी'।
- सांख्यिकी दिवस हर साल वर्तमान राष्ट्रीय महत्व की थीम के साथ मनाया जाता है।

प्रशांत चंद्र महालनोबिस

- प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद् थे जिन्होंने वर्ष 1932 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की थी।
- वे एक प्रशिक्षित भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने अपने शिक्षक डब्ल्यूएच मैकाले के कहने पर 'बायोमेट्रिका' पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही उनका आँकड़ों के प्रति झुकाव शुरू हुआ। इस पुस्तक से प्रभावित होकर उन्होंने पत्रिका के संस्करणों का एक पूरा सेट खरीदा।
- उन्हें जल्द ही पता चला कि मौसम विज्ञान और नृविज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया जा सकता है, और यह उनके वैज्ञानिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
- डॉ. महालनोबिस ने सांख्यिकी में कई योगदान दिए, जिसमें 'महालनोबिस दूरी' भी शामिल है, जो एक सांख्यिकीय माप है। इसके अलावा, वह भारत में मानव विज्ञान या मानव माप के अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी थे और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण और नमूनाकरण विधियों के डिजाइन में सहायता करते थे।
- उन्होंने फेल्डमैन-महालनोबिस मॉडल भी बनाया, जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त आर्थिक विकास का एक नव-मार्क्सवादी मॉडल था, जिसने देश में तेजी से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया।
- महालनोबिस ने भारत के पहले योजना आयोग में भी कार्य किया। उन्हें पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार भी मिले।

रवींद्रनाथ टैगोर के साथ संबंध:

- वे पहली बार 1910 में शांतिनिकेतन में मिले।
- महालनोबिस के एक करीबी सहयोगी रवींद्रनाथ टैगोर ने सांख्य के दूसरे खंड में लिखा, "ये समय और स्थान के क्षेत्र में संख्याओं के नृत्य चरण हैं, जो उपस्थिति के भ्रम को बुनते हैं, परिवर्तन का एक निरंतर प्रवाह है जो कभी नहीं होता है।
- महालनोबिस ने प्रतिष्ठित बंगाली पत्रिका प्रोबाशी के लिए 'रवींद्र परिचय' ('रवींद्र का परिचय') नामक निबंधों की एक श्रृंखला लिखी।
- पीसी महालनोबिस ने भी विश्व भारती की स्थापना में रवींद्रनाथ टैगोर की मदद की।

कालक्रम:

- **1930:** पहली बार 'महलनोबिस दूरी' प्रस्तावित की गई थी, जो दो डेटा सेटों के बीच तुलना के लिए एक उपाय है।
- कई आयामों में माप के आधार पर एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी को खोजने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह क्लस्टर विश्लेषण और वर्गीकरण के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **1932:** कोलकाता में आईएसआई की स्थापना, जिसे वर्ष 1959 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था।
- **1933:** 'सांख्यः द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स' की शुरुआत।
- **1950:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना और सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की स्थापना।
- **1955:** योजना आयोग के सदस्य बने और 1967 तक इस पद पर रहे।
- उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में औद्योगीकरण और विकास के लिए रोडमैप तैयार किया।
- **1968:** पद्म विभूषण से सम्मानित।
- उन्हें अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था।

स्वदीप कुमार

इंटरनेट शटडाउन

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) के कार्यालय ने इंटरनेट शटडाउन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की: इसके रुझान, कारण, कानूनी प्रभाव और मानव अधिकारों पर प्रभाव, और कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन लोगों की सुरक्षा करता है और कल्याण प्रभावित होता है, सूचना प्रवाह बाधित होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

इंटरनेट शटडाउन:

- इंटरनेट शटडाउन उपायों का उपयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब नागरिक अशांति होती है, सरकारी कार्यों के संबंध में सूचना के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए।
- शटडाउन में अक्सर इंटरनेट कनेक्टिविटी या प्रभावित सेवाओं तक पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना शामिल होता है। हालाँकि, सरकारें तेजी से बैंडविड्थ को कम करने या मोबाइल सेवा को 2G तक सीमित करने का सहारा लेती हैं, जिससे नाममात्र की पहुंच बनाए रखते हुए इंटरनेट का सार्थक उपयोग करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
- दुनिया भर की सरकारों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट बंद करने का सहारा लिया है
- इससे वीडियो, लाइव प्रसारण और अन्य पत्रकारिता कार्यों को साझा करना और देखना मुश्किल हो जाता है जिन्हें अक्सर नागरिक समाज आंदोलनों, सुरक्षा उपायों के साथ-साथ चुनाव कार्यवाही के दौरान आदेश दिया जाता है, और मानवाधिकार निगरानी और रिपोर्टिंग को गंभीरता से कम किया जाता है।

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे:

- इंटरनेट शटडाउन कई मानवाधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा और सूचना तक पहुंच को तेजी से प्रभावित करता है, जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए लोकतांत्रिक समाजों की नींव में से एक के रूप में एक शर्त है।
- यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और अन्य मानवाधिकार उपकरणों (यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में गारंटीकृत अन्य सभी अधिकारों के लिए एक मानदंड है।
- सतत विकास लक्ष्य अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों से मुक्त, सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध और सुलभ इंटरनेट के माध्यम से कार्य करने के लिए राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों को सुदृढ़ करते हैं।
- संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) मानकों को अपनाने पर काम करता है जो सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क और प्रौद्योगिकियां आपस में जुड़ती हैं और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती हैं।

प्रमुख निष्कर्ष:

वैश्विक परिदृश्य:

- पहला बड़ा इंटरनेट शटडाउन जिसने दुनिया का ध्यान खींचा वह 2011 में मिस्र में था, और इसके साथ सैकड़ों गिरफ्तारियां और हत्याएं भी हुई थीं।
- #KeepItOn गठबंधन, जो दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन एपिसोड की निगरानी करता है, ने 2016-2021 तक 74 देशों में 931 शटडाउन का दस्तावेजीकरण किया।
- उस अवधि के दौरान 12 देशों द्वारा 10 से अधिक शटडाउन लागू किए गए थे। वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में कई शटडाउन का सामना करना पड़ा है, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट एशिया और अफ्रीका में रही हैं।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा दायर किए गए शटडाउन में से 132 को आधिकारिक तौर पर अभद्र भाषा, प्रचार या अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के अन्य रूपों के प्रसार को नियंत्रित करने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया था।

भारतीय परिदृश्य:

- भारत ने 106 बार इंटरनेट कनेक्शन को अवरुद्ध या बाधित किया है और भारत में जम्मू और कश्मीर में कम से कम 85 इंटरनेट शटडाउन एपिसोड हैं।
- 2016-2021 तक नागरिक समाज समूहों द्वारा दर्ज किए गए सभी शटडाउन में से लगभग आधे विरोध और राजनीतिक संकट के संदर्भ में थे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान 225 शटडाउन शामिल थे।

चुनाव के दौरान बंद:

- यह डिजिटल उपकरणों तक पहुंच को समाप्त करता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक प्रवचन को बढ़ावा देने, मतदान और चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- अकेले 2019 में, 14 अफ्रीकी देशों ने चुनावी अवधि के दौरान इंटरनेट तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया।
- ये व्यवधान निष्पक्ष पत्रकारों और सामान्य रूप से मीडिया के काम को बाधित करते हैं। युगांडा में शटडाउन ने हिंसक दमनकारी उपायों की रिपोर्टों के बीच 2021 में चुनावों के मीडिया कवरेज को कमजोर कर दिया।
- चुनाव अवधि के दौरान विरोध के बाद बेलारूस और नाइजर जैसे देशों में भी शटडाउन की सूचना मिली थी।

इंटरनेट बंद का असर:

- **आर्थिक गतिविधि पर:** यह सभी क्षेत्रों के लिए भारी आर्थिक लागत का कारण बनता है, वित्तीय लेनदेन, वाणिज्य और उद्योग को बाधित करता है।
- विश्व बैंक ने हाल ही में गणना की है कि पिछले एक दशक में हुई आर्थिक प्रगति को उलटते हुए, फरवरी-दिसंबर 2021 से अकेले म्यांमार में इंटरनेट बंद करने की लागत लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **शिक्षा पर:** यह सीखने के परिणामों को कमजोर करता है और शिक्षकों, स्कूल प्रशासकों, परिवारों के बीच शिक्षा योजना और संचार में हस्तक्षेप करता है।

स्वास्थ्य और मानवीय सहायता तक पहुंच पर:

- अध्ययनों ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर शटडाउन के महत्वपूर्ण प्रभावों को दिखाया है, जिसमें तत्काल चिकित्सा देखभाल जुटाना, आवश्यक दवाओं और उपकरणों के रखरखाव को बाधित करना, चिकित्सा कर्मियों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करना और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल है।

- इंटरनेट शटडाउन का मानव एजेंटों की सहायता प्रदान करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और वितरण के लिए महत्वपूर्ण सूचना के प्रवाह को बाधित किया जा सकता है।
- म्यांमार में इंटरनेट बंद होने से स्थानीय सहायता संगठनों को कथित तौर पर संकट में डाल दिया, क्योंकि इससे उन्हें धन की मांग करने और प्राप्त करने से रोका गया था।

इंटरनेट शटडाउन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:

- जैसा कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासित किया गया है कि इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। यह एक उचित प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है और इसे तभी लागू किया जाना चाहिए जब सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा हो। कुछ संतुलन परीक्षण किया जाना चाहिए और सरकार को अत्यंत आवश्यक होने पर ही इस अत्यंत प्रतिबंधात्मक उपाय का उपयोग करना चाहिए।

स्वदीप कुमार

'पे रोल ऑटोमेशन' (PADMA)

भारतीय तटरक्षक बल के लिये एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 'मासिक भत्तों के वितरण के लिये पे रोल ऑटोमेशन' (PADMA) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वेतन और भत्तों का निर्बाध एवं समय पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु PADMA नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने वाला एक स्वचालित मंच है।
- वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक, नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा और यह मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्त्वावधान में विकसित किया गया है ।

- **महत्त्व:**
  - इस पहल की नींव रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय द्वारा मंत्रालय के तहत सभी संगठनों के लिये **'वन स्टॉप पे अकाउंटिंग'** समाधान प्रदान करने के लिये रखी जा रही है।
  - PADMA के लॉन्च से **डिजिटल इंडिया** विज़न की अवधारणा को मज़बूती मिलेगी। साथ ही यह एक **'आत्मनिर्भर भारत'** पहल है क्योंकि पूरे मॉड्यूल को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों ने डिज़ाइन और विकसित किया है।
- **भारतीय तटरक्षक बल:**
  - **रक्षा मंत्रालय** के अंतर्गत भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव एजेंसी है, इसका **क्षेत्राधिकार** इसके **निकटवर्ती क्षेत्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित अपने क्षेत्रीय जल पर है।**
    - **सन्निहित क्षेत्र:** क्षेत्रीय समुद्र के बाहरी किनारे बेसलाइन से 24 समुद्री मील तक फैला होता है।
    - **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)**: एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (**SEZ**) एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं।

- ICG का गठन 1971 के युद्ध के बाद **रुस्तमजी समिति** की सिफारिशों के आधार पर किया गया।
- **प्रमुख कार्य:**
  - ICG के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक समुद्री मार्गों से तस्करी को रोकना है।
    - सन्निहित क्षेत्र और **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर इसका अधिकार क्षेत्र है।
  - बाढ़, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों को सहायता प्रदान करना ।
  - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और अपने अधिकार वाले क्षेत्र के साथ ही **हिंद महासागर क्षेत्र** में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु तटवर्ती देशों के साथ भी सहयोग करता है।
  - महासागरों में व्यावसायिक संबंधों का विकास करने हेतु **सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR)** तथा **नेबरहुड फर्स्ट**' (Neighborhood First) की नीति के तहत ICG महासागर शांति स्थापना के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संबंध स्थापित किये हैं।

केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली

भारत में **केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली** में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) **प्रणाली** और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) **प्रणाली** किसी भी अन्य **प्रणाली** के रूप में शामिल होंगे जिस पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

- **RTGS:** यह बड़े लेन-देनों के लिये लाभार्थियों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है।
- **NEFT:** यह एक देशव्यापी भुगतान प्रणाली जहाँ 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा है।
- विकेंद्रीकरण भुगतान प्रणाली में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन व्यवस्था [चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)] के साथ-साथ अन्य बैंक [एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ECCS) केंद्रों की जाँच] और किसी अन्य प्रणाली के रूप शामिल होंगे जिसमें समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  - **चेक ट्रंकेशन:** यह भुगतानकर्त्ता बैंक द्वारा भुगतानकर्त्ता बैंक शाखा के रास्ते में किसी बिंदु पर ड्रॉअर द्वारा जारी किये गए भौतिक चेक के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया है।

YOJNA IAS

रवि सिंह